(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि देश के दूर-दराज तथा पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क संचार का अभाव है और वहां मिडिल तथा हाई स्कूल 15-20 किलोमीटर दूर हैं और पैदल चल कर जाना पड़ता है, इसलिए लड़कियां अपनी पढ़ाई प्राथमिक या मिडिल स्तर पर छोड़ देती हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार प्रत्येक विकास खण्ड में कम से कम एक छात्रावास सहित एक स्कूल खोलने के लिए अनुदान देने का है ताकि लड़कियों को अपनी पढ़ाई प्राथमिक स्तर पर न छोड़नी पड़े और महिला शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रीय नीति वास्तविक रूप में लागू हो सके ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) यह शैक्षिक संस्थान कब तक खोले जाने की संभावना है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों की राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् द्वारा आयोजित (30 सितम्बर, 1978 की यथास्थिति के अनुसार) चौथे अखिल भारतीय शैक्षिक सर्वेक्षण के अनुसार 26.42% ग्रामीण जनसंख्या को 5 किलोमीटर के अन्दर मिडिल स्तर की कक्षाओं की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। इसी प्रकार से 81.2% ग्रामीण जनसंख्या के लिए 8 किलोमीटर के अन्दर उच्चतम माध्यमिक कक्षाओं की सुविधा उपलब्ध नहीं थी।

(ख) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

देश में निराश्रित विधवाओं/वृद्धों और विकलांगों की राज्य-वार संख्या

4946. **श्री हरीश रावत** : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय द्वारा देश में निराश्रित विधवाओं, वृद्धों और विकलांगों की संख्या का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है ; और

(ग) राज्यों द्वारा प्रतिवर्ष उनके कल्याण पर खर्च की जा रही धनराशि को देखते हुये सभी हकदार व्यक्तियों को कब तक लाभ मिलने की संभावना है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उप मंत्री (श्री पी०के० थुंगन) : (क) 1981 जनगणना ने वृद्धों के सम्बन्ध में जानकारी एकत्रित की है जिससे 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के व्यक्तियों का अनुमान लगाना सम्भव है। 1981 में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन ने विकलांग व्यक्तियों से सम्बन्धित एक सर्वेक्षण किया था। निराश्रित विधवाओं की संख्या का अनुमान लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

(ख) दो विवरण, एक 60 और इससे अधिक आयु के वृद्ध व्यक्तियों का अनुमान दर्शाने वाला और दूसरा विकलांग व्यक्तियों का अनुमान दर्शाने वाला, सभापटल पर रखे जाते हैं। [ग्रंथालय में रखे गये। **देखिये संख्या** LT-7613/83]

(ग) इन श्रेणियों के व्यक्तियों के कल्याण के के लिए तैयार की गई विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत सभी पात्र व्यक्तियों को शामिल करने के लिए कोई समयरचना निश्चित नहीं की गई है।

Planning for Ports

4947. **SHRI SATISH AGARWAL** : Will the Minister of SHIPPING AND TRANSPORT be pleased to state :

(a) whether there is a great need for Port Planning and properly co-ordinated and well matched cooperation for improving Port Performance Programmes in the country]; and

(b) if, so, what steps are being taken by the Central Government in regard thereto ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI Z.R. ANSARI) : (a) and (b). The need for planned development of major ports is fully recognized by the Government. To ensure a coordinated approach to planning, the user Ministries are also represented on the Working Groups set up under the directions of the Planning Commission for formulation of the Five Year Plans. The major ports' development schemes are taken up for implementation after they are approved and the requisite funds are provided in the Annual Plans.

As regards performance, the productivity of the ports is monitored closely.

Expenditure on Integrated Child Development Scheme and its Working in Gujarat

4948. SHRI UTTAMBHAI H. PATEL : Will the Minister of SOCIAL WELFARE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a number of schemes and projects are being carried out in various parts of Gujarat and other States on Integrated Children Development Schemes ;

(b) if so, the details of schemes which were carried out from 1 December, 1980 to 30 June, 1983 ;

(c) the details of such schemes and projects proposed to be carried out during 1983, 1984 and 1985 ;

(d) what is the procedure etc., for monitoring the same ;

(e) how much amount have been spent on establishment, administration and development thereof during these years ; and

(f) how much amount have been incurred by any foreign agency towards these schemes ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRIES OF EDUCATION AND CULTURE AND SOCIAL WELFARE (SHRI P.K. THUNGON) : (a) Yes, Sir.

(b) During the years 1980-81 to 1982-83, a total of 22 new Centrally Sponsored Integrated Child Development Services (ICDS) Projects were sanctioned and the 7 old Centrally Sponsored ICDS Projects were continued.

(c) 18 additional Centrally Sponsored ICDS Projects are sanctioned for 1983-84 and 1984-85 and the 29 old centrally sponsored projects are continued.

(d) Integrated Child Development Services Projects are monitored closely through monthly progress reports obtained from each project and quarterly progress reports obtained from the State Governments. Assistance of All India Institute of Medical Sciences and the Medical Colleges is also taken in the monitoring of health and nutrition components of the programme.

(e) During the period 1980-81 to 1982-83, total grants of Rs. 1.83 crores were given by the Central Government to the Government of Gujarat for the ICDS Programme. This includes 3% provision for establishment at State and District levels. These figures do not include expenditure on training and supplementary nutrition.

(f) UNICEF provides assistance for consultancy, training, supplies, equipment, monitoring, research and evaluation. USAID assistance will be utilised for 11 ICDS Projects in Panchmahals District, Gujarat, for 6 years, commencing from the current year. CARE and WFP food commodities are also utilised in some ICDS Projects. Most of the assistance is received in kind.

Scheduled Caste and Scheduled Tribe Officials in UGC and Central Universities

4949. SHRI K. ARJUNAN : Will the Minister of EDUCATION AND CULTURE be pleased to state :

(a) total strength of the officials in University Grants Commission and in each